उत्तराखण्ड राज्य का प्रमुख हिन्दी मासिक ई – समाचार पत्र (डिजिटल पेपर) E- mail : janabhivyakti123@gmail.com

जन अभिव्यक्ति

www.janabhivyakti.com

खबर की तह ...

वर्ष : 1, अंक : 1 | 1 मार्च 2026 | हल्द्वानी (नैनीताल) | पृष्ठ : 4

जब अपने ही दामन झटक कर चल दिए, तो गैरो से क्या गिला

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निजीकरण का कहर

हल्द्वानी। इन दिनों प्रदेश मै संचालित हो रहे किसी न किसी कॉरपोरेट अस्पतालों के उद्घाटन में सत्ता के नामचीन चेहरों की मौजूदगी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हल्द्वानी में एक निजी हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सहित भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे, जिसने इस कार्यक्रम को भव्यता का रूप तो दिया। लेकिन यह भव्यता सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ सकती। यहां बता दे कि इसी उद्घाटन स्थल से महज कुछ कदमों की दूरी पर स्थित सरकारी डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल संकटों से जूझ रहा है। यहां की स्थिति यह है कि कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अस्पताल में संसाधनों की भारी कमी के साथ साथ डॉक्टरों की भारी किल्लत है, और मरीजों की बढ़ती भीड़ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को पूरी तरह चरमरा कर रख दिया है । यह सरकारी अस्पताल जो न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के मरीजों को भी इलाज प्रदान करता था, अब अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। अब यह साफ दिखने लगा है कि सरकार सरकारी

करने के बजाय निजीकरण को बढ़ावा दे रही है? यहां सवाल यह भी है कि क्या सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी संस्थानों को आगे बढ़ने का मौका मिले? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे हमेशा निजी संस्थानों के उद्घाटन या निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने तक सीमित रहते हैं, और इन आयोजनों का खर्च सरकारी खजाने से चलता है। यह विरोधाभास न सिर्फ सरकारी तंत्र पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जनता से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या इस तरह की योजनाओं का सरकार के वास्तविक उद्देश्यों से कोई लेना-देना है, या फिर भ्रष्टाचार और निजीकरण के नाम पर एक साजिश रची जा रही है? कुल मिलाकर, सरकारी तंत्र में पाई जाने वाली यह अराजकता और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें आज के दौर की सबसे बड़ी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत चुनौती बन चुकी हैं।

अपनी कहानी खुद लिखो

हल्द्वानी। महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर भी है। यह वह समय है जब हम समाज में स्त्री की भूमिका, उसकी चुनौतियों और उसकी संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करते हैं। आज की स्त्री शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, राजनीति और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है, परंतु इसके बावजूद जीवन की छोटी-छोटी उलझनों में वह कई बार अपने ही आत्मविश्वास को भीतर कहीं दबा देती है। परिवार, संबंधों और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच वह अक्सर स्वयं को अंतिम स्थान पर रख देती है। अवसर उसके सामने आते हैं, पर असमंजस, संकोच और परिस्थितियों की जटिलता उसे ठहरने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि स्त्री अपने अस्तित्व को कैसे पहचान पाए? जैसा कि कहा गया है स्वतंत्रता का पहला कदम बाहर नहीं, मन के भीतर उठता है। वास्तविक परिवर्तन भी यहीं से शुरू होता है। जब स्त्री अपने भीतर के डर, संकोच और असमंजस को पहचानकर उनसे आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, तभी वह अपनी कहानी की सच्ची लेखिका बनती है। दरअसल, जीवन हमें अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को पहचानने और सही दिशा देने का साहस हमें स्वयं ही जुटाना होता है। इसी संदर्भ में यह बात बहुत सार्थक लगती है, जो स्त्री अपने निर्णय स्वयं लेने लगती है, वही अपने भाग्य की लेखिका बन जाती है। स्त्री

ललिता कापड़ी

की वास्तविक स्वतंत्रता उसी दिन होगी, जब वह मानसिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता उसे निर्णय लेने का आत्मविश्वास देती है और मानसिक स्वतंत्रता उसे सही-गलत का विवेक प्रदान करती है। परंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिस्पर्धा या अनुकरण न बन जाए। यदि इतिहास में पुरुषों ने कुछ गलतियां की हैं, तो उन्हें दोहराना स्त्री की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। सच्ची स्वतंत्रता वह है जो विवेक, मर्यादा और संतुलन के साथ आगे बढ़े। आज सोशल मीडिया के दौर में अभिव्यक्ति के अनेक मंच उपलब्ध हैं। महिलाएँ पहले से कहीं अधिक सक्रिय होकर अपनी प्रतिभा और विचारों को सामने ला रही हैं। यह परिवर्तन सकारात्मक है और प्रेरणादायक भी। परंतु इस अभिव्यक्ति के साथ यह समझना भी आवश्यक है कि हमारा प्रदर्शन समाज और आने वाली पीढ़ी को क्या दिशा दे रहा है। दरअसल, यह प्रश्न केवल स्त्री का नहीं है, पुरुष का भी है। समाज का संतुलन तभी संभव है जब दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझें। प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है कि स्त्री और पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। इसी संदर्भ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिस्पर्धा से समाज नहीं बनता, पूरकता से सृष्टि आगे बढ़ती है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा। यदि कुछ बड़ा है तो केवल अहम। और जब इस अहम से 'अ' हट जाता है, तो वह 'हम' बन जाता है। यही हम परिवार को जोड़ता है, समाज को बनाता है और सृष्टि को सुंदर बनाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री और पुरुष दोनों यह समझें कि वे एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी हैं। जब दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, तब ही एक संतुलित और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव होता है। इस महिला दिवस पर यही संदेश है, स्त्री को किसी और की कलम का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी कहानी स्वयं लिख सकती है, साहस से, विवेक से और आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि जब स्त्री अपनी कहानी खुद लिखती है, तब केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि समाज की दिशा भी उज्ज्वल हो जाती है।

नैनीताल में न्याय की डिजिटल उड़ान

ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ, एआई से मिलेगी अधिवक्ताओं को नई ताकत

नैनीताल। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल में गुरुवार को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित डिजिटल ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे न्यायिक कार्यप्रणाली को गति देने वाली ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों से प्रतिदिन आने वाले आदेशों और निर्णयों की त्वरित जानकारी अधिवक्ताओं और वादकारियों दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिला न्यायाधीश ने कहा कि डिजिटल संसाधनों के माध्यम से अधिवक्ता नवीनतम फैसलों और विधिक तथ्यों से तुरंत अवगत हो सकेंगे जिससे न्याय प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद ने इस पहल को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि ई-लाइब्रेरी में उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से जुड़े 27 लाख से अधिक प्रकरणों का डाटाबेस उपलब्ध है इससे अधिवक्ताओं को शोध कार्य में व्यापक सहायता मिलेगी जिससे समय की बचत भी होगी। एसोसिएशन के सचिव दीपक रूवाली ने बताया कि डिजिटल ई-लाइब्रेरी अत्याधुनिक एआई फीचर से लैस है इसमें सिविल क्रिमिनल सर्विस ट्रिब्यूनल और एन.आई. एक्ट सहित विभिन्न प्रकार के मामलों में प्रश्न पूछने पर त्वरित और सटीक उत्तर प्राप्त किए जा सकेंगे साथ ही याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों की ड्राफ्टिंग में भी यह प्रणाली बेहद उपयोगी सिद्ध होगी नई व्यवस्था से नैनीताल की न्यायिक कार्यप्रणाली में तकनीकी क्रांति का आगाज माना जा रहा है अधिवक्ताओं ने इसे डिजिटल युग की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी कदम बताया है जिससे न्याय व्यवस्था और अधिक सुलभ सरल और प्रभावशाली बनेगी। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शंकर सिंह चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता मान सिंह बिष्ट, हरिशंकर कंसल, मनीष मोहन जोशी, राजेश चंदोला, सुशील शर्मा, पंकज बिष्ट, प्रीति साह, मंजू कोटलिया, बलवंत सिंह थलाल, हरीश भट्ट, प्रदीप परगाई, चंद्रेश ममगई, भरत भट्ट, ओंकार गोस्वामी, संजय सुयाल, अर्चित गुप्ता, संजय सिंह बिष्ट, भानु प्रताप मौनी, गंगा सिंह बोरा, शारीक अली, नीरज गोस्वामी, मो बिलाल, गौरव कुमार, अनिल बिष्ट, नीलेश भट्ट, गौरव भट्ट, चंद्रकांत बहुगुणा, उमेश कांडपाल, शिवांशु जोशी, निखिल बिष्ट, कमल चिलवाल, सुभाष जोशी, प्रदीप प्रसाद, तारा आर्या, दीपक दत्त, मोहन नाथ गोस्वामी, जयंत नैनवाल, मुन्नी आर्या, सरिता बिष्ट, किरन आर्या, आरती,

कामिनी गंगवार, जया आर्या, भावना जंतवाल, मीनाक्षी, तानुप्रिया जोशी, दिव्या, बार क्लर्क आनंद चंद्रा आदि मौजूद रहे।

गांव की समस्याओं का गांव में ही समाधान करने का होना चाहिए प्रयास : डॉ. हरीश सिंह बिष्ट

भीमताल। भीमताल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश सिंह बिष्ट ने ग्राम पंचायत जंतवाल गांव में आयोजित खुली बैठक में प्रतिभाग किया। साथ ही गांव में निर्माणाधीन विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान हेमा जंतवाल ने की। डॉ. बिष्ट ने ग्रामीणों की पेयजल, सड़क , राशन,स्वयं सहायता समूह के आउटलेट उद्यान की समस्याओं का मौके पर निस्तारण कराया। ग्रामीणों ने जंगली जानवर बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की माग की। ब्लॉक प्रमुख ने संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। प्रमुख ने कहा कि अधिकारियों का भी प्रयास होना चाहिए कि ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रतिभाग करे, ताकि अधिकांश ग्रामीणों कि समस्या का निराकरण मौके पर ही हो। बैठकों में जाने से वहां की समस्या का

बेहतर रूप से पता चलता है। समाज कल्याण से संबंधित वृद्धावस्था, विकलांग से संचालित योजनाओं के प्रस्ताव पारित हुए। साथ ही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के चयन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया। जलागम विभाग के अधिकारी ने बताया कि जंतवाल गांव में कृषि उद्यान कार्य, उद्यान कार्य, भूमि संरक्षण के कार्य किए जाएंगे खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड से संबंधित राशन कार्ड का निरीक्षण किया। विद्युत विभाग की लो वोल्टेज की समस्या प्रमुखता से उठी। बैठक के पश्चात निर्माणाधीन मशरूम यूनिट का निरीक्षण किया जिसके निर्माण से ग्रामीणों को स्वरोजगार मिलेगा शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सदस्य विपिन जंतवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम सिंह जंतवाल, बीडीसी अजय जंतवाल, प्रधान प्रकाश आर्य, शेखर भट्ट, कुंदन जीना, कमल जंतवाल,प्रताप सिंह, दिवान सिंह, आन सिंह, ईश्वर जंतवाल, पूर्व प्रधान रमेश राम, विशन राम, बीडीओ हर्षित गर्ग, भूपाल बिष्ट, जल संस्थान हर्षित कुमार, समाज कल्याण दिनेश बिष्ट, लोक निर्माण विभाग प्रवीण कुमार, संजय कुमार, सीमा रावत, लता सुयाल, जलागम अशोक कुमार, सहित अन्य ग्रामीण विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

होली की रंगारंग धूम से सराबोर रहा आईन प्रोग्रेसिव स्कूल, लामाचौड़

हल्द्वानी। आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल, लामाचौड़ में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर रंग-बिरंगे गुलाल, फूलों और आकर्षक सजावट से सुसज्जित रहा। विद्यार्थियों ने पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात छात्रों ने होली गीतों, समूह नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। छोटे बच्चों ने 'रंगों की होली' पर मनमोहक कविता-पाठ किया, जिसे खूब सराहा गया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल होली मनाने का संदेश दिया। सभी को प्राकृतिक रंगों के प्रयोग तथा जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। पूरे वातावरण में उल्लास और अपनत्व की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

विद्यालय परिवार ने यह संकल्प लिया कि वे हर त्योहार को सामाजिक संदेश और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मनाते रहेंगे।

फाइनेंशियल पॉलिटिक्स

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को नि:शुल्क बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) सरकार के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनी की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। बिजली वितरण कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में विद्युत संशोधन नियम, 2024 के एक नियम को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की चीजें देकर राज्य सरकारें लोगों की आदतें खराब कर रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि इन लोगों का रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कई राज्य सरकारें कर्ज और घाटे से दबी हुई हैं। इसके बावजूद वे मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने पूछा कि बिजली शुल्क अधिसूचित होने के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक जेब ढीली करने का फैसला क्यों किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा राज्यों को रोजगार के रास्ते खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन देना शुरू कर देंगे, फिर मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देंगे, तो कौन काम करेगा और फिर कार्य संस्कृति का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वैलफेयर के तौर पर आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो बिजली का चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं उठा सकते, उनके बीच फर्क किए बिना, आप बांटना शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें अनुमान के मुताबिक, राज्य का कुल बकाया कर्ज बढ़कर 10.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस बढ़ते कर्ज के लिए वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र तमिलनाडु में वित्तीय अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी नहीं दे रही है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का फंड रोक रही है। उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर भी निराशा जताई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु पर देश में सर्वाधिक 8.34 लाख करोड़ रुपये कर्ज है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इस पर 7.69 लाख करोड़ रुपये कर्जा है। इसी तरह महाराष्ट्र पर 7.22 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल पर 6.58 लाख करोड़ रुपये, कर्नाटक पर 5.97 लाख करोड़ रुपये, राजस्थान पर 5.62 लाख करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश पर 4.85 करोड़ रुपये का कर्जा है। गुजरात पर 4.67 लाख करोड़ रुपये, केरल पर 4.29 लाख करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश पर 4.18 लाख करोड़ रुपये, तेलंगाना पर 3.89 लाख करोड़ रुपये, पंजाब पर 3.51 लाख करोड़ रुपये, हरियाणा पर 3.36 लाख करोड़ रुपये, बिहार पर 3.19 लाख करोड़ रुपये और असम पर 1.51 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। वर्ष 2016-17 के बाद कर्ज पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई। वोट बैंक की राजनीतिक के कारण ऐसी लोकलुभावन मुफ्त की योजनाओं के कारण छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश डेब्ट ट्रैप में फंस गया है। आलम यह है कि हिमाचल सरकार के पास लिए गए कर्ज की मूल रकम व उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। वहीं, कर्ज लेने की लिमिट सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपए है। अगले वित्तीय वर्ष में कर्ज व ब्याज चुकाने के लिए 13 हजार करोड़ चाहिए। अब लोन को चुकाने के लिए मार्केट से कर्ज लेकर भी बात नहीं बन रही और तीन हजार करोड़ रुपए अपने बजट से चुकाने होंगे। सोलहवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हिमाचल सहित अन्य कुछ राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) खत्म कर दी है। इससे हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी चोट लगी है। हिमाचल प्रदेश पर कुल देनदारियां 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई हैं, जिससे यह पहाड़ी राज्य कर्ज लेने वाले भारतीय राज्यों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्स्टेट फाइनेंसश रिपोर्ट (2025-26) में कहा है कि मुफ्त की ऐसी योजनाओं के चलते राज्यों के बजट पर दबाव बढ़ रहा है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे (सड़क, स्कूल, अस्पताल) पर खर्च कुल बजट का 10 प्रतिशत से भी कम रह गया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने में कोई पीछे नहीं है। केंद्र में बतौर विपक्षी पार्टी आलोचना करने वाली कांग्रेस अपनी सत्ता वाले राज्यों में खुल कर श्रेवड़ियांश बांटती रही है। उसी तरह केंद्र में खुल कर यह काम करने वाली भाजपा, राज्यों में कांग्रेस व अन्य पार्टियों का इसके लिए विरोध करती है। बीते नौ साल में प्रति व्यक्ति कर्ज तीन गुना बढ़ गया है। इसका एक बड़ा कारण केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जनता को खुले आम श्रेवड़ियांश बांटना भी है। देश में प्रति व्यक्ति कर्ज 1,86,206 रुपए हो जाने का अनुमान है। अहम बात यह है कि राजनीतिक दलों को यह भी बताना चाहिए कि इन मुफ्त की योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा। अब हमारी फाइनेंशियल पॉलिटिक्स में ईमानदारी और जवाबदेही वापस लाने का समय आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने ली अफसरों की बैठक

हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य विभागों के साथ समन्वयन बैठक कर तैयारियां आरभ कर दी हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में प्रशासन, रेलवे एवं नगर निगम, प्राधिकरण, ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया। साथ ही रेलवे के अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित जानकारी ली गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरांत सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में, तत्समय सौपी गयी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि माननीय न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। बैठक में सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, आयुक्त नगर निगम परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी, गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित डी आर एम रेलवे (वी. सी. के द्वारा) एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हल्द्वानी शहर के नजदीक बाघ ने महिला को बनाया निवाला, जंगल में मिला क्षत-विक्षत शव

हल्द्वानी। हल्द्वानी शहर के नजदीक फतेहपुर रेंज के पनियाली जंगल में लापता हुई महिला का शव बरामद होने से क्षेत्र में दहशत है। जंगल में पहले महिला की चप्पल, दराती, कपड़े और खून के निशान मिले थे, जिसके बाद बाघ के हमले की आशंका जताई जा रही थी। सर्च अभियान के दौरान महिला का क्षत-विक्षत शव जंगल के अंदर से बरामद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला कमला फर्त्याल रोज की तरह जंगल में घास और लकड़ी लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की तो जंगल में उसकी चप्पल, दराती और कपड़े बिखरे मिले। आसपास खून के धब्बे पाए गए, जिससे जंगली जानवर के हमले की आशंका गहरा गई। बताया जा रहा है कि बाघ ने महिला के शरीर को बुरी तरह नोच डाला था और आधा हिस्सा खाया हुआ मिला। घटना की सूचना के बाद वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित ग्रामीण खुद ही जंगल में सर्च अभियान में जुट गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्गम क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों ने शव को डंडे पर बांधकर जंगल से बाहर निकाला। इस दौरान क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गश्त बढ़ाने तथा आदमखोर बाघ को पकड़ की मांग की। वन विभाग के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्राथमिक जांच में बाघ के हमले के संकेत मिले हैं। क्षेत्र में पिंजरा लगाने, कैमरा ट्रैप सक्रिय करने और गश्त बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों को अकेले जंगल न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को संयम बरतने और अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा है कि मामले की जांच जारी है तथा आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने कहा कि पनियाली (फतेहपुर वन क्षेत्र) में श्रीमती कमला फर्त्याल को बाघ द्वारा मारा जाना अत्यंत दुःखद ही नहीं, बल्कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की घोर विफलता है। इससे पहले गांधी आश्रम क्षेत्र में भी ऐसी घटना हो चुकी है। हर बार आश्वासन दिए जाते हैं, पर कार्रवाई शून्य रहती है। आखिर कब तक हमारे क्षेत्रवासी बाघ और गुलदार का शिकार बनते रहेंगे? क्या सरकार केवल घटनाओं के बाद बयान देने तक सीमित है? स्पष्ट चेतावनी है यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई कर आदमखोर को पकड़ा या समाप्त नहीं किया गया, तो वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय, फतेहपुर में अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी।

डिजिटल मोड के द्वारा पहली बार मोबाइल एप्स के माध्यम से एकत्र किया जायेगा डेटा

हल्द्वानी। भारत की जनगणना 2027 को लेकर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को जिला जनगणना अधिकारीध अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस काठगोदाम में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य जनगणना कार्य को सही, समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा करना है। जिला जनगणना अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ने बताया डिजिटल मोड के द्वारा पहली बार डेटा मोबाइल ऐप्स के माध्यम से एकत्र किया जायेगा जिसके लिए प्रगणक तथा पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं मोबाइल प्रयोग में लाया जायेगा। जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली सी.एम.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। जनगणना के प्रथम चरण में (मकान सूचीकरण और आवास गणना) 25 अप्रैल से 24 मई 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। द्वितीय चरण की जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी जिसमें जनसंख्या की गणना होगी साथ ही उत्तराखण्ड के हिम आच्छादित क्षेत्रों में 11 सितम्बर से 30 सितम्बर के मध्य होगी तथा आम जनता अपना डेटा सीएमएमएस पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपलोड कर सकते हैं इसके लिए 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक स्वजनगणना समयावधि निर्धारित की गई है।

अपर जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनगणना 2027 के प्रशिक्षण में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल जनगणना ऐतिहासिक है जो भी कार्य करें बिना भेदभाव के करें और कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों उपनिदेशक जनगणना प्रवीन कुमार ने जनगणना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारियां दी और प्रशिक्षण ले रहे चार्ज अधिकारियों का समाधान मौके पर किया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा जनगणना के विवरण के साथ ही राष्ट्रीय योजना एवं नीति निर्माण में इसका महत्व के बारे में जानकारी दी साथ ही जनगणना पदाधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व, चार्ज अधिकारी, प्रगणकों, पर्यवेक्षकों के दायित्व के बारे मे अहम जानकारियां दी। प्रशिक्षण में नगर आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारीध्सहायक जिला जनगणना अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी मास्टर ट्रेनर शिवानी जेटली, नितीश रावत, के साथ ही जनपद के समस्त तहसीलदार, नगर पंचायत, नगर पालिका, परिषद कैटोमेंट के अधिकारी तकनीकी सहायकों, सेन्सस क्लर्क आदि मौजूद थे।

पांच हजार रिश्वत लेते सांख्यिकी विभाग के अधिकारी को किया गिरफ्तार

देहरादून।सांख्यिकी विभाग के अधिकारी संजय कुमार को सीबीआई ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामला दर्ज कर गुप्त रूप से जांच कर रही थी। शिकायतकर्ता एक टैक्स एडवोकेट ने सीबीआई को भेजी शिकायत में बताया था कि वह अपने क्लाइंट की कंपनी के टैक्स से जुड़े काम देखते हैं। शिकायत के अनुसार, उनके क्लाइंट की कंपनी बीएस इंडस्ट्रीज को एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (एएसआई) की वार्षिक रिटर्न दाखिल करना थी। यह काम सांख्यिकी विभाग के माध्यम से किया जाता है। आरोप है कि देहरादून स्थित नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के सीनियर ऑफिसर संजय कुमार ने रिटर्न तैयार करने और जमा कराने के बदले पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक अधिकारी ने उन्हें व्हाट्सएप पर एक मोबाइल नंबर भेजकर उस नंबर पर यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की गोपनीय जांच की। प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने की बात सही पाए जाने पर अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद सीबीआई टीम ने आरोपी अधिकारी को ट्रैप कर रंगेहाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया।

एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कड़ा रुख

थाना प्रभारियों को लगाई फटकार, अपराध समीक्षा में जवाबदेही तय

- होली एवं रमजान पर्व पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हुड़दंग व जबरन रंग लगाने वालों पर पैनी नजर।
- 39 पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित, पुलिस परिवार के 14 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप राशि देकर किया उत्साहवर्धन।
- एसएसपी नैनीताल के स्पष्ट निर्देश काम नहीं तो दाम नहीं की नीति के तहत पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली में लाया जाएगा सुधार।

हल्द्वानी। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कोतवाली मीटिंग हॉल में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया। बैठक में जनपद की कानून-व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं और आगामी त्योहारों को लेकर अत्यंत कड़े निर्देश जारी किए गए। गोष्ठी से पूर्व एसएसपी ने कर्मचारी सम्मेलन के माध्यम से पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि यदि क्षेत्र में अपराध होता है, तो बीट कॉन्स्टेबल से लेकर हल्का प्रभारी तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।ड्यूटी के दौरान मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग करने और कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध 'नो वर्क नो पे' की नीति अपनाई जाएगी। महिला अपराध, साइबर ठगी और नशे के विरुद्ध अभियानों में तेजी लाने के साथ ही हिस्ट्रीशीटरों की निरंतर निगरानी और सत्यापन के निर्देश दिए गए। नशे में ड्राइविंग, स्टंट और ओवरस्पीडिंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। रात्रि चेकिंग में एल्कोमीटर का अनिवार्य प्रयोग होगा। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु एसएसपी ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए। जबरन रंग लगाने, शराब पीकर उत्पात मचाने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर तत्काल कठोर कार्रवाई होगी। अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए सोशल मीडिया सेल को सक्रिय कर दिया गया है। होली ड्यूटी में महिला पुलिसकर्मियों को पिकेट, मोबाइल और पैदल गश्त (चीता) में विशेष रूप से तैनात किया जाएगा। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से शांति समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने हेतु एसएसपी महोदय ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। उत्कृष्ट सेवा सम्मान, सराहनीय कार्य करने वाले 39 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें उप निरीक्षक दामोदर कापडी, हेड कांस्टेबल संजय सुयाल, कांस्टेबल आर्मोरर गोकुल धपोला, सुनील टम्टा, फायरमैन नीरज बालियान, फायरमैन विपिन कम्बोज, फायरमैन त्रिलोक बिष्ट, कांस्टेबल संजय नेगी, गोविन्द मेहरा, अमित ठाकुर, दीपक रौतेला, बलवन्त बिष्ट, एसओ जगदीप सिंह नेगी, उप निरीक्षक सोमेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक केवल राम, उप निरीक्षक गौरव जोषी, उप निरीक्षक मोहन सौन, अपर उपनिरीक्षक दान सिंह, कांस्टेबल हिमांशु गुणवंत, अनुचर अमित, विवेकानन्द, हेड कांस्टेबल अभिसूचना सुरेन्द्र बथियाल, कांस्टेबल शेखर सिंह बिष्ट, महबूब आलम, अमित कुमार, एएसआई (एम) सुलेमान, दफ्तरी दान सिंह, कांस्टेबल दीपक कुमार, देवेन्द्र सिंह सामन्त, दीप चन्द्र, विनोद आर्या, कांस्टेबल खड़क सिंह, तारा कम्बोज,महबूब अली, हेड कांस्टेबल त्रिलोक रौतेला, विशन राम, कांस्टेबल चालक बसन्त कुमार, कांस्टेबल चन्दन सिंह नेगी, हेड कांस्टेबल पीटी गौरव कोहली शामिल रहे। पुलिस परिवार के 14 मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉलरशिप राशि प्रदान की गई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। मेधावी विद्यार्थियों में नवनीत तिलारा, रोहित नाथ गोस्वामी, अंजली फर्त्याल, नम्रता राणा, तनीश राणा, तनवी रौतेला, हिमांशी चंद्र, कनक सैनी, कृषिका पांडे, मयंक सिंह, नमन सिंह मर्तोलिया, देवांश बिष्ट, तनुजा भट्ट तथा आदित्य शर्मा आमजन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। होली का पर्व शांतिपूर्ण मनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गोष्ठी के दौरान एसपी नैनीताल डॉ.जगदीश चन्द्र, एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, एसपी संचार रेवाधर मठपाल', सीओ हल्द्वानी अमित कुमार, सीओ रामनगर सुमित पांडे, सीओ नैनीताल रविकांत सेमवाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार, सीओ (प्रशिक्षु) विनय सिंह, सीओ (प्रशिक्षु) अंकित थपलियाल, प्रतिसार निरीक्षक हरकेश सिंह, निरीक्षक एलआईयू ज्ञानेंद्र शर्मा, राजकुमार बिष्ट प्रतिसार निरीक्षक पुलिस दूरसंचार समेत सभी थाना/ चौकी/ शाखा/ यातायात/ सीपीयू प्रभारी/ पीएसी प्रभारी/ एसडीआरएफ प्रभारी एवं पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

दूषित पानी की आपूर्ति से जीवन दूभर

द्वारीखाल (पौड़ी)। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना का लाभ सिमल्या गांव के बाशिंदों को साफ और शुद्ध पानक नहीं मिल पा रहा है। एकमात्र हैंडपंप से दूषित पानी की आपूर्ति होने से क्षेत्र के करीब दो दर्जन परिवारों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। द्वारीखाल प्रखंड के तहत ग्राम सिमल्या में जल आपूर्ति के लिए एक सार्वजनिक हैंडपंप लगा है। इससे करीब एक वर्ष से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। कई परिवार इसी हैंडपंप से मिलने वाले पानी पर निर्भर हैं। पानी गंदा होने के बावजूद इसका उपयोग करना मजबूरी बना हुआ है। पानी को उपयोग में न लाएं तो जलापूर्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है। स्वच्छ पानी के लिए ग्रामीणों को करीब तीन किलोमीटर दूर कीर्तिखाल स्थित जलस्रोत तक जाना पड़ता है। वहीं, कीर्तिखाल में भी लगे दो से तीन हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं। जलापूर्ति की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महिला गयाली देवी ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं का ज्यादा समय खेती और पशुओं के लिए चारापत्ती लाने में ही निकल जाता है। इसके बाद पीने के पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। इससे दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दूषित पानी के कारण पेट संबंधी दिक्कतों के साथ कई परिवार हैंडपंप पर हैं निर्भर, स्वच्छ पानी के लिए जा रहे हैं तीन किमी दूर ही हर समय बीमारी का डर सताता रहता है। संबंधित विभाग को कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जल्द समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं, ग्राम प्रधान अर्चना नेगी ने बताया कि समस्या को लेकर विभाग को बार-बार अवगत कराया गया लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। इस बाबत प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर हैंडपंपों की दशा सुधारने और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से क्षेत्रीय ग्रामीणों को स्वच्छ जल मुहैया कराने की मांग की गई है। समय रहते दूषित पानी की आपूर्ति बंद नहीं हुई तो जनस्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए संकल्पबद्ध है सरकार : पुष्कर सिंह धामी

- नंदा गौरा योजना के तहत 33 हजार से अधिक बेटियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंची राशि
- एक क्लिक के जरिए 1 अरब 45 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि का हुआ हस्तातंरण

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश की 33,251 बालिकाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,45,93.00 (एक अरब पैंतालीस करोड़ तिरान्नबे लाख रुपए) की धनराशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन्म के समय बेटा-बेटी के बीच होने वाले भेदभाव को समाप्त करते हुए, कन्या जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार नंदा गौरा योजना संचालित कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा बालिका के जन्म पर 11 हजार रुपए और बेटी के 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए 51 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अब तक 3,77,784 (तीन लाख सत्तर हजार सात सौ चौरासी) बालिकाओं को कुल 11,68,49.00 रुपए (ग्यारह अरब अडसठ करोड़ उनपचास लाख) की धनराशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है, साथ ही शिक्षित होने के बाद रोजगार के लिए भी बेटियों को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके बाद अब सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड की महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है, इससे सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति ज्यादा बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए भी प्रदेश की आम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नंदा गौरा योजना कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करने के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है। इस मौके पर विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि, इस वर्ष लाभांवित होने वाली बालिकाओं में 5913, नवजात हैं, जबकि शेष 27338 को 12वीं पास करने पर यह धनराशि मिली है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर सचिव चंद्रेश कुमार, विभागीय निदेशक बंशीलाल राणा सहित अन्य अधिकारी कम्रचारी उपस्थित हुए।

अब मरीजों को मिलेगा निशुल्क इलाज

महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने हल्द्वानी में चार आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया शुभारम्भ

हल्द्वानी। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्रांतर्गत भगवानपुर, दमुवाढुंगा, नारायण नगर बिठौरिया और गोकुल नगरी कुसुमखेड़ा में महापौर गजराज बिष्ट ने अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। महापौर गजराज ने बताया कि हल्द्वानी-काठगोदाम में 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे है। जिनमें प्रशिक्षित एमबीबीएस चिकित्सकों की टीम द्वारा केंद्र पर प्रतिदिन सामान्य रोगों की जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके साथ ही आवश्यक दवाइयाँ, गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, वरिष्ठ नागरिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच तथा एनसीडी (हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं कैंसर) की प्राथमिक जांच एवं परामर्श की सुविधाएँ भी प्रदान की जाएँगी। इन सभी सेवाओं के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह केंद्र राज्य एवं निकाय सरकार की संयुक्त पहल के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र विशेष रूप से उन क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ गरीब, निर्धन एवं श्रमिक वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिन्हें पूर्व में दूरी अथवा आर्थिक कारणों से अस्पतालों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इन केंद्रों के माध्यम से उनके घर के समीप ही आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य असमानता कम होगी तथा समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह केंद्र हल्द्वानी जैसे उभरते नगर की बड़ी आबादी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

यहाँ नागरिकों को उपचार के साथ-साथ स्वास्थ्य जागरूकता, पौष्टिक आहार, स्वच्छता एवं निवारक उपायों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर निगम द्वारा केंद्र के सुचारु संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँगी। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि डॉ. अशोक चौहान ने जानकारी दी कि यह केंद्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड प्रणाली लागू की गई है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य डेटा सुरक्षित रहेगा और भविष्य के उपचार में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ उपचार के साथ-साथ जनजागरूकता, निवारक स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नगर, सुरक्षित नागरिक का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब प्रत्येक नागरिक अपनी सेहत के प्रति जागरूक होकर नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराए। इससे पूर्व में रामपुर रोड़ देवलचौड़ और गौजाजाली में भी दो केंद्र खोले जा चुके है।

इस अवसर पर नगर आयुक्त परितोष वर्मा, मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा कंचन उप्रेती, स्थानीय पार्षद तनुजा जोशी, दीपक बिष्ट, सुरेंद्र मोहन नेगी, प्रमोद पंत, धीरज पाण्डेय, अरुण टम्टा, महेश जोशी, पूर्व सैनिक गोविंद बरती, सोबन भड़, अशोक चौहान, डॉ मनोज काण्डपाल सहित सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

महिला की चेन छीनने में एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार

पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में बंगापानी के तोली गांव में महिला की चेन छीनने के आरोप में पुलिस ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र और एक महिला को गर्जिया पुल के पास से गिरफ्तार किया है। छात्र के साथ गई महिला मेडिकल प्रोफेशन ने जुड़ी बताई जा रहा है। पुलिस ने छीनी गई चेन बरामद कर ली है। पुलिस को दी तहरीर में 38 वर्षीय ममता देवी ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह घर से सरसों निकालने खेत जा रही थी। सड़क किनारे बाइक पर खड़े एक युवक और युवती ने नेटवर्क न होने की बात कहते हुए मोबाइल फोन मांगा। 50 मीटर पैदल चलने के बाद युवक ने ममता को बलपूर्वक पकड़ और साथ आई युवती ने गले से सोने की दो मालाएं छीन लीं। महिला का दावा है कि माला का वजन एक से डेढ़ तोला तक है। एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि आरोपी युवक 25 वर्षीय सन्नी सिंह थाना मियांवाली नगर पश्चिमी विहार, दिल्ली है जबकि 23 वर्षीय युवती हिमानी बोरा हल्द्वानी की निवासी है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

स्वामी गिरीश चन्द्र चन्दोला केयर ऑफ श्री सीमान्त वैष्णव डिफेन्स कॉलोनी नियर डीएवी स्कूल से प्रकाशित। संपादक : गिरीश चन्द्र चन्दोला, मो. नं. : 8077248363
Email : janabhivyakti123@gmail.com (ई समाचार पत्र से जुड़े समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।)

धामी कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को दी मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी है। जिसमें संशोधन करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है। कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी है। आगामी विधानसभा सत्र में 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा, लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए। सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी मौन पालन नीति 2026 को मिली मंजूरी, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया।उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन, शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी। संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती, उत्तराखंड राज्य में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग हेतु नीति 2026 को मिली मंजूरी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया संशोधन। अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को

सदन का पटल पर रखने को मिली मंजूरी। उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मिली मंजूरी। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मिली मंजूरी। विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी। उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुर्नस्थापित करने को मिली मंजूरी, उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को मिली मंजूरी, उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुर्नस्थापित किए जाने को मिली मंजूरी। समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को मिली मंजूरी। उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को मिली मंजूरी। उत्तराखण्ड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 (1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को 5000/- प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनो से नामित 02 सदस्यों को 3000/- प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल सवर्ग का पुर्नगठन किए जाने को मिली मंजूरी। देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी। नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 01 और जिला न्यायालयो के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों के नए पदों को सृजित किए जाने पर बनी सहमति। विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड में बेहतर सेवा वितरण के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु कियान्वयन के लिए स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन और प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी। उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2026 को मिली मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में तदर्थ / अनुबन्ध / संविदा/आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 04 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एल०टी०) विशेष शिक्षा शिक्षक के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने की विकास कार्यो की समीक्षा

हल्द्धानी में चल रहे विकास कार्यो को दो शिफ्ट में करने के निर्देश

हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में यूयूएसडीए, सिंचाई, जल संस्थान, पेयजल निगम,विद्युत, जल संस्थान एवं एचपीसीएल आदि विभागों द्वारा शहर में कराए रहे विभिन्न विकास कार्यों जिसमें सडक चौडीकरण, सीवर लाईन,पेयजल एवं गैस पाईप लाईन,सड़क चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण, यूटिलिटी डक्ट सिफ्टिंग आदि महत्वपूर्ण विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि हल्द्वानी शहर को आधुनिक एवं सुविधायुक्त भव्य बनाने हो जो भी विकास कार्य वर्तमान में किए जा रहे हैं, उन कार्यों को दोगुनी गति से कराया जाय इस हेतु दो शिफ्टों में दिन में एवं रात्रि में भी कार्य हों, इस हेतु जिलाधिकारी ने यू यू एस डी ए के अधिकारियों को दोगुनी क्षमता में कार्य करने हेतु मैन पावर को बढ़ाते हुए रात्रि में भी कार्य करने के निर्देश दिए। इस हेतु बैठक में कार्यदाई संस्था को कार्य का लक्ष्य देते हुए 13 मार्च तक इन कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिलाधिकारी ने सभी कार्यदाई संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक सप्ताह बैठक कर जो भी समस्या कार्यों में आ रही हैं, उनका समाधान मौके पर ही करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि एनओसी से सम्बन्धित जो भी समस्या हैं बैठक में ही समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहर में जहां भी सडक, सीवर एवं पेयजल के कार्य हो रहे है उन कार्यों को योजनाबद्व तरीके से करें। उन्होंने कहा शहर में जिन आन्तरिक मार्गों में सडक, सीवर पेयजल आदि के कार्य प्रगति पर है उन्हें पूर्ण करने के उपरान्त ही दूसरे क्षेत्रों में कार्य करें ताकि आमजनता को कोई परेशानी ना हो। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से कहा कि जिन क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है,सुरक्षा के दृष्टिगत उन स्थानों पर साईनेज बैरिकेटिंग,लाइटिंग एवं सैंडबैग का इस्तेमाल अवश्य किया जाए ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनों से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मैनेजर यू.यू.एस.डी.ए. कुलदीप सिंह को निर्देश दिये शहर में कुसुमखेडा चौराहा,लामाचौड, हनुमान मन्दिर तथा मण्डी निकट शनिबाजार चौराहा का अतिक्रमण मुक्त हो गया है। इन चौराहों पर डीपीआर के तहत सौन्दर्यीकरण कार्य 13 मार्च 2026 से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने

कहा कि जिन आन्तरिक क्षेत्रों में पेयजल, सीवर लाईन आदि के कार्य पूर्ण हो चुके है। उन क्षेत्रो में सडक का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें इसके उपरान्त ही नये क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ किया जाए। बैठक में परियोजना प्रबन्धक ने मण्डी गेट नियर शनिबाजार चौराहे के सम्बन्ध में बताया कि मुख्य मार्ग पर पुलिस चौकी है तथा उक्त चौराहे पर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस चौकी को मण्डी गेट के समीप शिफ्ट करना है इस हेतु 25 लाख की धनराशि मण्डी परिषद को दो दिन में हस्तांतरित किया जाय, ताकि चौराहे का चौड़ीकरण शीघ्र किया जा सके। जिलाधिकारी ने पुलिस, नगर आयुक्त यूयूएसडी,सिंचाई आदि विभागों को संयुक्त निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये। सडक चौडीकरण योजनाबद्व तरीके से किया जायेगा, जिलाधिकारी, प्रथम चरण तीनपानी से मण्डीगेट का चौडीकरण होली के बाद किया जायेगा। इसके उपरान्त तीनपानी से कालटैक्स तक चौडीकरण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा चौडीकरण के दौरान साथ-साथ विद्युत पोल, जलसंस्थान,पेयजल पाईप लाईनों को भी शिफ्टिंग करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों की भूमि पर अतिक्रमण है वह विभाग शीघ्र ही अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगे इसके लिए विभाग को प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सहयोग किया जायेगा। उन्होंने कहा तिकोनियां से काठगोदाम तक जितने भी वृक्ष सडक की जद में आ रहे है उन्हें लापिंग किया जाए एवं पीपल के पेडों को अन्यत्र शफ्टिंग की योजना पर शीघ्र कार्य किया जाए। इसमें वन विभाग का सहयोग भी लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन सडकों पर आवागमन काफी होता है उन सडकों को प्राथमिकता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा प्रत्येक 10 दिन में कार्यों की समीक्षा की जायेगी। इसके लिए अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।

जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत काठगोदाम से तुमडियाडाम तक बनने वाली नहर के सम्बन्ध में शीशमहल के पास फिल्टर हाउस का पानी नहर में आने से कार्य व्यवधान होने पर परियोजना निदेशक जमरानी ने बताया कि शेष पानी को गौला नदी मे डाइवर्ट किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया इस समस्या का समाधान आपसी समन्वय के साथ करें ताकि शहर के लोगों को पेयजल की परेशानी ना हो। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कार्य हो रहा है उन क्षेत्रों में कार्यदायी संस्था द्वारा कोई साइनेज बोर्ड, सैंडबैग, रिफलेक्टर आदि नही लगाये गये हैं साथ ही सडक का मलवा भी नही हटाया गया है जिससे दुर्धटना हो सकती है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मैनेजर यूयूएसडीए एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों मे कार्य हो रहा है उन क्षेत्रों मे साइनेज के साथ ही सडक मार्ग का मलवा कार्य के साथ-साथ हटाना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा, एस. पी. सिटी मनोज कत्याल,सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार, अधिशासी अभियंता यूपीसी एल एसके गुप्ता, पेयजल निगम एके कटारिया, सिंचाई दिनेश सिंह,लोनिवि प्रत्युष कुमार आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

विदा हुई रे शुभ होली तू

ललिता कापड़ी

विदा हुई रे शुभ होली! तू, आशीष सभी को दे जाना,
जो सूने रह गए मन के आँगन, उनमें आश जगा जाना।

मिलन रह गया अगर कहीं, पथ भी सूने रह गए होंगे,
उन बिछड़े हृदयों में फिर से, रंग-प्रेम का सजा जाना।

रूठे रिश्तों की देहरी पर धूल अगर जम सी बैठी,
फागुन बनकर कोमल-कोमल स्नेह-दीप जला जाना।

कुछ आँखों में स्वप्न अधूरे, कुछ होठों पर मौन पड़ा,
उनके भीतर छिपी व्यथा को हँसकर गले लगा जाना।

जो ऊँच-नीच की दीवारें अब भी मन में उठती हैं,
उन पर मानवता का सुंदर इंद्रधनुष बना जाना।

जो जाति-धर्म के नामों पर बँटते रहते घर-आँगन,
उनके बीच प्रेम का सच्चा सेतु एक बना जाना।

बरसाने की राहों में यदि राधा अब भी तन्हा हो,
श्याम को उसके प्रेम का सच्चा अर्थ बता जाना।

अयोध्या के आँगन में फिर ऐसा पावन सवेरा हो,
फिर कोई वनवास न आए, ऐसा सुमंगल रचा जाना।

जो प्रेम-अगन धीमी पड़ती इस जग के व्यवहारों से,
अपने चटकीले रंगों से उसको पुनः स्फूर्ति दे जाना।

व्याकुल मन की विनती सुन ले,अगली फागुन-रातों में,
प्रेम-मिलन का आशीष लिए फिर से धरा पे आ जाना।

फर्जी प्रवेशपत्र बनाकर बोर्ड परीक्षा दिलाने के मामले में प्रधानाचार्य गिरफ्तार

हरिद्वार। हरिद्वार के रानीपुर पुलिस ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में फर्जी प्रवेशपत्र बनाकर छात्रा से परीक्षा दिलाने के आरोप में एक प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया है। उसने ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा के परिजनों से रुपये लेकर पास कराने का झांसा दिया था। आरोपी ने छात्रा का फर्जी प्रवेशपत्र तैयार कराया और उसके स्थान पर दूसरी छात्रा को परीक्षा दिलवा दी। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। चंगेज निवासी ज्वालापुर को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने स्वयं को ज्वालापुर स्थित अल्मोडिया इस्लामिक हाईस्कूल का प्रिंसिपल बताया।

साथ ही द सक्सेज प्वॉइंट नाम से व्हाट्सएपध्सोशल मीडिया ग्रुप के जरिये ऑनलाइन कोचिंग चलाने की बात भी स्वीकार की। उसने ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा के परिजनों से परीक्षा पास कराने के नाम पर धनराशि ली और एक अन्य छात्रा की फोटो का उपयोग कर फर्जी प्रवेशपत्र तैयार कराया। उसी प्रवेशपत्र के आधार पर वास्तविक परीक्षार्थी की जगह दूसरी छात्रा को परीक्षा में बैठाया गया। आरोपी को धोखाधड़ी, कूटरचना और सार्वजनिक परीक्षा में प्रतिरूपण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली प्रभारी आशुतोष राणा ने बताया कि 24 फरवरी को राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महदूद में हाईस्कूल परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण का मामला सामने आया था। इस संबंध में कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेश चन्द्र द्विवेदी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने तीन युवक और चार युवतियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से फर्जी प्रवेशपत्र बरामद किए थे। इस मामले की जांच भी जारी है।